# महाभियोग नोटिस को ठुकराना न्यायपालिका की स्वतंत्रता नष्ट करने वाला कदम- येचुरी

**नई दिल्ली**- माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला कदम बताया है। येचुरी ने आज नायडू के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा ''भाजपा सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर न्यायपालिका का गला घोंटने की कोशिश पहले से ही कर रही है, अब महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने की दिशा में नया कदम है।''

उल्लेखनीय है कि नायडू ने कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा और भाकपा सहित सात दलों के सदस्यों द्वारा न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ 20 अप्रैल को सौंपे गये महाभियोग प्रस्ताव को आज नामंजूर कर दिया। नायडू ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ लगाये गये आरोपों का आधार पुख्ता नहीं है इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। येचुरी ने इसे जल्दबाजी में किया गया फैसला बताते हुये ट्वीट कर कहा ''सात दलों के सांसदों के प्रस्ताव को ठुकराना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। भाजपा सरकार संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर सभी लोकतांत्रिक रास्तों को नष्ट भ्रष्ट कर रही है। बजट सत्र में पेश अविश्वास प्रस्ताव के मामले में भी यही हुआ था। यह संविधान को नष्ट करना नहीं है तो और क्या है।''

एक अन्य ट्वीट में येचुरी ने कहा कि अगर सभापति महाभियोग के नोटिस में वर्णित आरोपों की जांच स्वयं गुणदोष के आधार पर कर लेंगे तो इस हेतु गठित होने वाली जांच समिति क्या करेगी। यही वजह है कि इससे पहले महाभियोग के किसी नोटिस को कभी सभापति द्वारा खारिज नहीं किया गया। उन्होंने कहा ''विपक्षी दल भारत के संविधान के संरक्षण और उसकी मूल भावना के अनुकूल पालन सुनिश्चित कराने के लिये हर संभव कदम उठायेंगे।''

# किम जापान के साथ 'किसी भी समय' वार्ता के लिए तैयार

**सोल**-दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने आज कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन 'किसी भी समय ' जापान के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। इससे पहले तोक्यो ने चिंता जाहिर की थी कि प्योंगयांग से सुलह के प्रयासों में उसे दरकिनार कर दिया गया है। इसके बाद सोल ने यह टिप्पणी की है। किम ने शुक्रवार को सीमावर्ती गांव पनमुंजोम में ऐतिहासिक शिखर बैठक में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात की थी। एशिया में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी जापान का रुख प्योंगयांग के साथ बातचीत को लेकर हमेशा कड़ा रहा है लेकिन हालिया राजनयिक प्रगति की स्थिति में वह खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सोल से उत्तर कोरिया से बातचीत की मंशा जाहिर की थी। किम इयू - क्योम ने संवाददाताओं को बताया, ''राष्ट्रपति मून ने किम को बताया कि प्रधानमंत्री आबे उत्तर कोरिया से बात करना चाहते हैं और ... जापान एवं उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते को सामान्य बनाने की मंशा रखते हैं।'' उन्होंने बताया, ''किम ने कहा कि उत्तर कोरिया जापान से किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है।''

प्रवक्ता ने बताया कि मून ने आबे को उत्तर कोरियाई नेता के जवाब के बारे में रविवार सुबह फोन कर अवगत करा दिया है।

# न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर फिर से विचार के लिए शीघ्र होगी कॉलेजियम की बैठक

**नई दिल्ली**-समझा जाता है कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश के रुप में प्रोन्नति के लिए उनके नाम पर फिर से विचार करने के मकसद से शीघ्र ही कॉलेजियम की बैठक बुलाने का फैसला किया है। सरकार ने शुक्रवार को संबंधित फाइल कॉलेजियम को लौटा दी थी जिसने दस जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में प्रोन्नति के लिए सिफारिश की थी। उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि अब कॉलेजियम की बैठक होनर स्वभाविक है और यह यथाशीघ्र बुलायी जाएगी। बहरहाल, अब सवाल कॉलेजियम के पांचों न्यायाधीशों की उपलब्धता का है क्योंकि कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर

चिकित्सा कारणों से 26-27 अप्रैल को काम पर नहीं आए थे। अधिकारी ने बताया कि यदि कोरम पूरा रहता है तो कॉलेजियम की बैठक तत्काल बुलायी जाएगी।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने उस पीठ की अगुवाई की थी जिसने वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने न्यायमूर्ति जोसेफ की प्रोन्नति संबंधी कॉलेजियम की सिफारिश उसके पास पुनर्विचार के लिए लौटा दी। उसने कहा कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मापदंड के अनुरुप नहीं है और उच्चतम न्यायालय में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, न्यायमूर्ति जोसेफ केरल से आते हैं।

न्यायमूर्ति जोसेफ जुलाई , 2014 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह इस साल जून में 60 साल के हो जाएंगे। उन्हें 14 अक्तूबर, 2004 को केरल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्होंने 31 जुलाई, 2014 को उत्तराखंड उच्च न्यायलय का प्रभार संभाला था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर की थी।

# मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है- सोनिया

**नई-दिल्ली**-कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की संस्थाओं को कमजोर करने और वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में परिवर्तन की आंधी के आसार हैं। पार्टी की 'जन आक्रोश' रैली में सोनिया ने कहा, 'मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है। मोदी जी ने जो वादे किए, वो पूरे नहीं हुए।' पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने कहा, 'आप लोग (कार्यकर्ता) जिस गर्मजोशी से यहां आए हैं उससे साबित होता है कि देश मे परिवर्तन की आंधी के आसार हैं। उन्होंने कहा, % देश में परेशानी का माहौल है। छोटे कारोबारी, किसान, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक सभी परेशान हैं। दो करोड़ नौकरियों का वादा किया गया लेकिन आज युवा परेशान है। सभी के साथ धोखा हुआ है।'

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और महंगाई बढ़ गई है।सोनिया ने सवाल किया, 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा .... इस दावे का क्या हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सत्ता हथियाने के लिए जो वादे किए गए थे वो सब खोखले साबित हुए।' उन्होंने कहा, 'देश हिंसक दौर से गुजर रहा है। संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। चुनाव को ध्यान में रखकर समाज को बांटा जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है।'

# प्रधानमंत्री ने छात्रों, युवाओं को स्वच्छ भारत इंटर्नशिप में हिस्सा लेने का सुझाव दिया

**नई-दिल्ली**- स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छात्रों एवं युवाओं को 'स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप' में हिस्सा लेने का सुझाव देते हुए कहा कि भारत सरकार के तीन मंत्रालयों ने युवाओं के लिये यह इंटर्नशिप शुरू की है जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र..छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के तीन मंत्रालय ... खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पेयजल मंत्रालय आदि ने मिलकर एक 'स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटनशिप 2018'' शुरू की है। उन्होंने कहा, '' कॉलेज के छात्र-छात्राएँ, एनसीसी और एनएसएस के नौजवान, नेहरु युवा केंद्र के युवा... जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना और कुछ सीखना चाहते हैं, समाज के बदलाव से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उसके निमित्त बनना चाहते हैं; जिनमें एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर समाज में कुछ-न-कुछ कर गुज़रने का इरादा है, उन सब के लिए अवसर है और इससे स्वच्छता को भी बल मिलेगा।''

मोदी ने कहा, 'जब हम 2 अक्तूबर से महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनायेंगे, उसके पहले हमें कुछ करने का संतोष मिलेगा। इसके तहत जो उत्तम-से-उत्तम इंटर्न होंगे, जिन्होंने कॉलेज में उत्तम काम किया होगा, विश्वविद्यालय में किया होगा -ऐसे सभी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाएँगे।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रत्येक इंटर्न को 'स्वच्छ भारत मिशन' की ओर से एक प्रमाणपत्र दिया जायेगा। इतना ही नहीं, जो इंटर्न इसे अच्छे से पूरा करेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें दो क्रेडिट प्वायंट भी देगा। उन्होंने कहा, ''मैं छात्रों को, छात्राओं को, नौजवानों को फिर एक बार निमंत्रण देता हूँ कि इंटर्नशिप का लाभ उठाएँ। आप 'माइ गॉव' पर जाकर 'स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे युवा स्वच्छता के इस आन्दोलन को और आगे बढ़ाएँगे।''प्रधानमंत्री ने परीक्षा के बाद छुट्टियों की योजना बना रहे छात्रों को इस नये काम के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने कहा कि आप अपनी जानकारियाँ, कहानी, फोटो, वीडियो ज़रूर भेजिए। एक नए अनुभव के लिए इन छुट्टियों को सीखने का अवसर बनायें। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने 'गुड न्यूज इंडिया' कार्यक्रम देखने का सुझाव भी दिया ताकि पता चल सके कि देश के किस-किस कोने में कितने-कितने लोग किस-किस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं।

# राहुल की खुर्शीद को नसीहत- जब पार्टी RSS के खिलाफ लड़ रही है तो मिलकर प्रयास करें

**नई दिल्ली**-कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और अहम चुनावों के पहले पार्टी को मुश्किल में डालने वाले बयान देने वाले नेताओं को आज इशारों-इशारों में नसीहत दी कि जब पार्टी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो सबको मिलकर प्रयास करना होगा। राहुल ने आज 'जन आक्रोश' रैली में कहा, ''कभी-कभी हमारी पार्टी में अलग अलग विचार होते हैं। यहां सलमान खुर्शीद जी बैठे हुए हैं। मैं यह मानने को तैयार हूं कि हमारी पार्टी में अलग अलग विचार होंगे और मैं अलग अलग विचारों को बढ़ावा दूंगा। मैं सलमान खुर्शीद की रक्षा करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जब पार्टी आरएसएस के खिलाफ लड़ रही है तो हमें एकसाथ मिलकर लड़ने का प्रयास करना है।'' उन्होंने कहा, ''भाजपा के अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी अपने मंच ऐसी बात कभी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी में सिर्फ एक सोच चल सकती है और वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच।''

राहुल ने कहा, ''उस पार्टी में न अरूण जेटली जी आदर होगा, न आडवाणी जी का आदर होगा और न ही उनके मुख्यमंत्रियों का आदर होगा।'' गौरतलब है कि पिछले दिनों खुर्शीद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एक कार्यक्रम में कहा था कि 'कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के दाग हैं।' उनके इस बयान से कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की किरकिरी हुई और भाजपा ने उस पर जमकर निशाना साधा। वैसे, यह कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के किसी नेता ने पार्टी को मुश्किल में डालने वाले बयान दिए हैं। पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'नीच' शब्द का इस्तेमाल किया था जिस वजह से कांग्रेस के लिए किरकिरी वाली स्थिति पैदा हो गई थी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक-रवि कुमार पोत्दार, 71/74, सुयश विहार, भमोरी दुबे, इन्दौर से प्रकाशित एवं आर्टटेक ग्राफिस, 864/9, नेहरु नगर, इन्दौर म०प्र० से मुद्रीत
प्रधान संपादक-रवि कुमार पोत्दार आर.एन.आई. नम्बर-12782/2003 e-mail- censortimes@ hotmail.com Mob No-9926631707